जनसत्ता

4 जून, 2019

नापाक हरकत

पाकिस्तान ने बीते शनिवार को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी के दौरान जो अशिष्टतापूर्ण हरकत की है, वह हैरान करने वाली तो है ही, निंदनीय भी है। आज तक ऐसी घटना शायद ही किसी मुल्क में देखने-सुनने में आई होगी जब इफ्तार पार्टी में पहुंचे मेहमानों को जबरन वापस लौटा दिया गया हो। भारतीय उच्चायोग ने इस्लामाबाद के सेरेना होटल में इफ्तार की दावत रखी थी। इसमें पाकिस्तान के तीन सौ से ज्यादा राजनीतिकों, सांसदों, राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, मीडिया से जुड़े दिग्गजों, कारोबारियों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान ने भाईचारे और सौहार्द के इस आयोजन को एक अप्रिय घटना में बदल डाला। जो मेहमान सेरेना होटल पहुंचे थे, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। ज्यादातर को तो होटल के भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया। सुरक्षा जांच के नाम पर सुरक्षाबलों, पुलिस और आइएसआइ के कारिंदों ने मेहमानों से धक्का-मुक्की की और उन्हें धमकाया भी गया। कई मेहमानों को सुरक्षाकर्मियों की गालियां सुननी पड़ीं, जांच के नाम पर कुछ के मोबाइल तक छीन लिए गए। पूरा होटल एक तरह से छावनी बना दिया गया था। इस घटना ने पाकिस्तान की मंशा और उसके चेहरे को उजागर करके रख दिया है। साफ है, वह इस आयोजन को किसी सूरत में नहीं होने देना चाहता था।

किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रमजान के पवित्र महीने में पड़ोसी देश भारत की ओर से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी एक दुखदायी घटना में बदल जाएगी। यह घटना बता रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत के साथ कैसे 'दोस्ताना' रिश्ते रखना चाहता है। जब-तब होती रहने वाली इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के बीच रिश्तों में और कड़वाहट पैदा करती रही हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने यह किया हो। पिछले दो-तीन साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। राजनयिकों के आवासीय परिसरों की जासूसी, बिजली-पानी की आपूर्ति बंद कर देने, संदिग्ध रूप से पीछा करने, राजनयिकों के यहां आने-जाने वालों को पूछताछ के नाम पर परेशान और प्रताड़ित करने जैसी घटनाएं अक्सर होती रही हैं। इन सारी घटनाओं के बावजूद भारत ने बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय दिया और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे तनाव भड़के और रिश्ते खराब हों। भारत ने हर ऐसी घटना पर राजनयिक प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के तहत ही विरोध दर्ज कराया। लेकिन पाकिस्तान ने तो राजनयिक आचरण और मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है!

इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान आखिर संदेश क्या देना चाहता है? क्या वह इस तरह भारत से अच्छे रिश्तों की उम्मीद करता है? पिछले साल पाकिस्तान की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने रिश्ते सुधारने की दिशा में बड़ी-बड़ी बातें की थीं। कहा था, अगर भारत एक कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान दो कदम बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस साल फरवरी में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हो गया। क्या ऐसा संभव है कि बिना पाकिस्तान सरकार या आइएसआइ के इशारे के इस तरह की घटना हो जाए? ताजा घटना से तो यही संकेत मिलता है कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में ऐसी हरकत की है। भारत की मजबूत सरकार के सख्त रवैए से उसकी नींद उड़ी हुई है और वह इस तरह की घटनाओं की आड़ में शांति की प्रक्रिया को बाधित करना चाहता है। अगर इरादे नेक हैं तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को क्या इस घटना की जांच करा कर हकीकत सामने नहीं लानी चाहिए!

मौत की चढ़ाई

एवरेस्ट की चढ़ाई दुनिया के सबसे साहसिक पर्वतारोहण अभियानों में से एक मानी जाती रही है। भौगोलिक स्थिति से लेकर मौसम तक को देखते हुए वहां जाने के पहले कई तरह की तैयारियां अनिवार्य होती हैं। साहस के साथ पहाड़ों की चढ़ाई का हौसला रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान कई तरह के खतरों से भरे उस सफर को एक सामान्य खेल की तरह मान लिया गया है। यही वजह है कि जानलेवा जोखिम की अनदेखी करके ऐसे लोग भी एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं, जिन्हें पर्वतारोहण की बुनियादी जानकारी तक नहीं होती। जबकि किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए विधिवत एक प्रशिक्षण से गुजरना और पूरी तरह प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। लेकिन महज शौक के साथ दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली चोटी पर चढ़ाई के लिए लोगों की भीड़ जिस तरह एवरेस्ट और उसके आसपास बढ़ रही है, वह न केवल कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है, बल्कि खुद एवरेस्ट और वहां के पर्यावरण तक के सामने कई तरह मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस साल हालत यह है कि कुछ दिनों पहले एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले रास्ते में भीड़ की वजह से जाम लग गया और लोगों को आगे बढ़ने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। सवाल है कि क्या यह किसी दुस्साहसिक अभियान की तस्वीर हो सकती है कि खतरे के सफर में इस कदर भीड़ हो जाए!

दरअसल, हाल के वर्षों में एवरेस्ट पर जाने के लिए जैसे-जैसे लोगों के बीच आकर्षण बढ़ा है, वैसे-वैसे इसने कारोबारी शक्ल अख्तियार कर ली है। दूसरी वजह यह है कि इस मौसम में एवरेस्ट पर जाने के लिए परमिट जारी करने से नेपाल को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा जमा करने का मौका होता है। गौरतलब है कि एक व्यक्ति को वहां जाने के लिए परमिट हासिल करने के बदले ग्यारह हजार डॉलर चुकाने पड़ते हैं। इस साल तीन सौ इक्यासी लोगों को एवरेस्ट चढ़ाई के लिए परमिट जारी किया गया। जबकि वहां जाने के लिहाज से मौसम की अवधि छोटी थी। नतीजतन, एक समय हालत यह हो गई कि एवरेस्ट की चढ़ाई के रास्ते पर ही लंबा जाम लग गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ के बीच पंद्रह किलोमीटर की रफ्तार से बहती बर्फीली हवा और ऑक्सीजन की कमी के बीच खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए घंटों खड़े लोगों की हालत कैसी होती होगी।

एक बड़ी मुश्किल यह है कि जिन लोगों के पास पर्वतारोहण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होता है, वे भी स्थानीय गाइड के सहारे चोटी पर चढ़ाई की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के प्रशिक्षण के अभाव के बावजूद एवरेस्ट फतह करने के शौक और विपरीत मौसम के दबाव के चलते इस साल अब तक ग्यारह लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। सवाल है कि क्या पर्वतारोहण के शौक में इतनी संख्या में लोगों की जान जाने को सही माना जा सकता है? एवरेस्ट पर चढ़ाई के शौक के कारोबार बनते जाने ने न सिर्फ वहां जाने वाले लोगों की जान को जोखिम में डाला है, बल्कि वहां लगने वाले कचरे के ढेर की वजह से खुद एवरेस्ट का पारिस्थितिकीय संतुलन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में यह जरूरी है कि न केवल एवरेस्ट फतह करने की इच्छा रखने वाले लोगों, बल्कि खुद एवरेस्ट को प्राकृतिक रूप में बचाए रखने के लिए वक्त पर जरूरी कदम उठाए जाएं। महज शौक या कारोबारी मुनाफे के लिए एवरेस्ट को जानलेवा चोटी के रूप में तब्दील नहीं होने दिया जाना चाहिए।

कल्पमेधा

लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि साधारण लोगों में असाधारण प्रतिभाएं होती हैं।

-हेनरी एमर्शन फास्डिक

ट्रंप के निशाने पर भारत

संजीव पांडेय

ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर दिया। भारत ईरान से रोजाना साढ़े चार लाख बैरल तेल आयात करता था। ईरान भारत को तेल आयात के बिल भुगतान के लिए साठ दिन का समय देता था। यह छूट दूसरे तेल निर्यातक देश नहीं देते हैं। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ भारतीय तेल बाजार पर नहीं है, वे भारत के रक्षा बाजार पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं।

पिछले कुछ समय में अमेरिकी प्रशासन का यह दूसरा झटका है। ट्रंप प्रशासन ने व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था के तहत भारत को मिलने वाले प्रशुल्क छूट के लाभ को समाप्त कर दिया है। भारत को यह छूट अमेरिका सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) के तहत विकासशील देशों को मिलने वाली छूट के तहत देता था। ट्रंप के इस फैसले से भारत का लगभग छह अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। अमेरिकी प्रशासन का यह फैसला भारतीय उद्योग जगत को झटका है। इससे भारत के कई उत्पाद अमेरिका में शुल्क लगने के कारण महंगे होंगे। इनकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता कम होगी। ट्रंप ने साफ किया है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी निर्यात के लिए खोले। अगर नहीं खोलेगा तो भविष्य में भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ट्रंप का कहना है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी सामान के लिए नहीं खोल रहा है। इसलिए पांच जून से भारत का लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा समाप्त करना उचित है। चीन के बाद अब भारत अमेरिका के निशाने पर है। वैसे तो अमेरिका भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना सहयोगी बताता रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को और बढ़ाएगा। यह शुरुआत है। ईरान से तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं।

भारतीय निर्यात को हतोत्साहित करने की नीति अपनाए जाने के संकेत ट्रंप प्रशासन ने पहले ही दे दिए थे। चीन के साथ ही ट्रंप के निशाने पर यूरोपीए यूनियन, भारत, जापान, कनाडा जैसे देश हैं। ट्रंप ने जब चीन से व्यापार युद्ध शुरू किया तो यूरोपीय यूनियन और भारत जैसे मुल्क खुश थे। इन्हें लग रहा था कि अमेरिकी बाजारों में चीनी निर्यात कम होने पर उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। यूरोपीय यूनियन का निर्यात सत्तर अरब डॉलर और जापान और कनाडा का निर्यात बीस-बीस अरब डॉलर तक बढ़ने की संभावना थी। भारतीय निर्यात में भी साढ़े तीन फीसद के इजाफे की उम्मीद थी। लेकिन भारत की यह खुशी सामान्य तरजीही व्यवस्था से बाहर होने के साथ ही खत्म हो गई। इसके संकेत पिछले दिनों भारत दौरे पर आए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रोस ने दे दिए थे। उनका कहना था कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर उच्च शुल्क लगा रहा है। भारत में नई सरकार के गठन के बाद अमेरिका इस मुद्दे को उठाएगा। भारत में आयात होने वाले अमेरिकी सामान पर औसत शुल्क 13.8 फीसद है। जबकि ऑटोमोबाइल पर साठ फीसद और मोटरसाइकिल पर पचास फीसद शुल्क है। कुछ अमेरिकी उत्पादों पर डेढ़ सौ से तीन सौ फीसद तक शुल्क भी लगाया जाता है। इससे अमेरिका खासा नाराज है।

अमेरिकी दबाव भारत को परेशान करने वाला है। हालांकि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने अमेरिकी तेल उद्योग से सालाना पांच अरब डॉलर के तेल और गैस आयात करने का फैसला किया। अमेरिकी उड्डयन उद्योग से भी भारत ने विमान खरीद का फैसला किया है। भारत अगले कुछ वर्षों में चालीस अरब डॉलर के विमान की खरीद करेगा। ट्रंप दुनिया के कई देशों पर दबाव बना कर अमेरिकी रक्षा उद्योग के बाजार का विस्तार कर रहे हैं। वे इससे व्यापार संतुलन भी अमेरिका के पक्ष में करना चाहते हैं। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों से परेशान जापान ने अपनी सेना के लिए अगले पांच साल में पचास अरब डॉलर के हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने का फैसला किया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ अमेरिकी रक्षा उद्योग को मिलेगा।

ट्रंप के दो फैसले भारतीय हितों के खिलाफ थे। ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर दिया। भारत ईरान से रोजाना साढ़े चार लाख बैरल तेल आयात करता था। ईरान भारत को तेल आयात के बिल भुगतान के लिए साठ दिन का समय देता था। यह छूट दूसरे तेल निर्यातक देश नहीं देते हैं। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ भारतीय तेल बाजार पर नहीं है, वे भारत के रक्षा बाजार पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। एक बार फिर अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से खरीदी जा रही एस-400 मिसाइलों को लेकर विरोध जताया है। यह सौदा पांच अरब डॉलर का है। अमेरिका ने साफ धमकी दी है कि रूस से एस-400 मिसाइल खरीदने से भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका ने साफ किया है कि अंतराष्ट्रीय बाजार में उच्च रूसी तकनीक से युक्त

रक्षा उपकरणों की खरीद पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। अगर भारत इसे खरीदेगा तो अमेरिकी कानूनों के तहत उसे भी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा।

अमेरिकी निर्यात के पांच बड़े बाजारों में कनाडा, मेक्सिको, चीन, जापान और ब्रिटेन हैं। आबादी के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। इसके बावजूद भारत अमेरिका के निर्यात बाजार की रैंकिंग में तेरहवें नबर है। अमेरिका कनाडा को सलाना तीन सौ अरब डॉलर, मेक्सिको को ढाई सौ अरब डॉलर, चीन को एक सौ तीस अरब डॉलर, जापान को सत्तर अरब डॉलर और ब्रिटेन को साठ अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है। जबकि भारत को सालाना तैंतीस अरब डॉलर का सामान बेचता है। अमेरिका की नजर भारत के मध्यवर्ग पर है। दरअसल, ट्रंप ने अमेरिकी निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिका में आयात होने वाले स्टील, अल्युमीनियम सहित हजारों वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की है। इससे दुनिया भर के स्टील, अल्युमीनियम, कपड़ा उद्योग के अलावा कई उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिकी कारपोरेशन सस्ते श्रम के लोभ में दुनिया के दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं। इससे अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। ट्रंप की कोशिश है कि अमेरिकी पूंजी का निवेश अमेरिका में ही हो, ताकि ज्यादा रोजगार पैदा हो। अमेरिकी शिक्षा उद्योग की नजर भी भारत पर है। अमेरिकी विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों की पसंद बन रहे हैं। भारतीय छात्रों से अमेरिकी शिक्षा जगत को सालाना पांच अरब डॉलर की आय हो सकती है।

भारत पर ताजा अमेरिकी दबाव के कुछ कूटनीतिक कारण भी हैं। ट्रंप भारत से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सिर्फ सहयोग ही नहीं चाहते, बल्कि चीन और रूस से भारत की दूरी भी बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल, ट्रंप एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा कर वे चीन और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। ईरान से तनाव बढ़ने की स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। इससे दोनों मुल्कों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। भारत अपनी जरूरत का अस्सी फीसद तेल आयात करता है। इसके अतिरिक्त ट्रंप एशिया में मजबूत हो रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को भी कमजोर करना चाह रहे हैं।

एससीओ के पीछे चीन और रूस का दिमाग है। एससीओ बीते कुछ समय में काफी मजबूत बन कर उभरा है, इससे अमेरिका खासा परेशान है। यह संगठन मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि एशियाई देशों के ऊर्जा संकट को भी दूर करेगा। इसमें दुनिया के दो बड़े देश चीन और भारत आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं, इससे भी अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि कई मुद्दों पर चीन और भारत के बीच आपसी तनाव है, पर आर्थिक सहयोग को लेकर दोनों मुल्कों में एक सहमति बन रही है। ट्रंप की परेशानी यह भी है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं। तुर्की भी ईरान के साथ है। इसलिए वे इन कूटनीति संबंधों के बीच एससीओ की मजबूती को कम करना चाहते हैं। भारतीय निर्यात पर मिली शुल्क छूट को समाप्त करने के पीछे ट्रंप प्रशासन की एक मंशा एससीओ को कमजोर करना भी हो सकती है।

धारणाओं की धुरी

चंदन कुमार चौधरी

दुनिया मेरे आगे

कुछ समय पहले दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम सुर्खियों में रहे। इस तरह की परीक्षाओं में कुछ विद्यार्थी काफी अच्छे नंबरों से, कुछ साधारण नंबरों से पास होते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। परिणामों पर कुछ दिनों तक चर्चा-परिचर्चा होती है, फिर सब शांत हो जाता है। लेकिन सच यह है कि साधारण दिखने वाली ऐसी घटनाएं दरअसल, साधारण नहीं होती हैं, बल्कि इनका दूरगामी परिणाम होता है। आमतौर पर यहीं से लोगों के मन में धीरे-धीरे सफल और असफल विद्यार्थियों को लेकर एक मानसिकता तैयार होने लगती है। भले ही यह एक परीक्षा का परिणाम होता हो, लेकिन इसे लोग जीवन में सफलता और असफलता का प्रमाण-पत्र मान कर चलने लगते हैं और तब यह बहुत खतरनाक हो जाता है। इसका जो ठप्पा विद्यार्थियों पर एक बार लग जाता है तो इससे वह शायद ही जीवन में कभी उबर पाता है।

ऐसे विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई-लिखाई से इतर कोई दूसरा काम भी करें तो लोग सफल बच्चों को सफल और असफल को असफल मान कर ही चलने लगते हैं। हालांकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर व्यक्ति पढ़ाई में सफल होता है तो वह जीवन की हर दौड़ में सफल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह जो व्यक्ति एक बार असफल हो गया, वह दूसरे काम में भी असफल ही होगा यह भी जरूरी नहीं है। एक साल अच्छा नंबर लाने वाला विद्यार्थी अगले साल अच्छा नंबर नहीं भी ला सकता है। जीवन में उतार-चढ़ाव लगा रहता है। सफलता और असफलता स्थायी नहीं होतीं। ऐसा लगता है कि अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों पर हमेशा बेहतर करने का दबाव बना रहता होगा। कई बार तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि अगर वह फिर अच्छा नंबर नहीं ला पाता है तो वह धीरे-धीरे अवसाद की दुनिया में भी चला जाता है। आए दिन विद्यार्थियों की खुदकुशी की खबरें आती ही रहती हैं।

वास्तव में समाज को खतरा प्रमाण-पत्र बांटने वाले ऐसे लोगों से है जो अपने निहित स्वार्थ और ईर्ष्या-द्वेष के कारण लोगों को निशाना बनाते हैं और उन्हें एक दायरे तक सीमित रखना चाहते हैं। ऐसे लोग अकेले या कई बार गुट में काम करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति की क्षमता असीम होती है और वह अगर चाहे तो अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसके लिए अगर एक कुशल प्रशिक्षक और मार्ग बताने वाला व्यक्ति मिल जाए तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आमतौर पर उसे मिलता है कुंठित व्यक्ति और समाज, जो उसे हतोत्साहित करने में लगा रहता है।

सच यह है कि हम लोग एक पूर्वधारणाओं या पूर्वाग्रहों से भरे समाज में जीते हैं। महिला है तो ऐसी होगी, दलित है तो ऐसा होगा, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है तो ऐसा ही होगा, दक्षिण भारत का है तो जरूर ऐसा होगा, पूर्वोत्तर का है तो ऐसा होगा आदि। समाज के लोग अपनी धारणा से सामने वालों के मनोभाव से खेलते हैं और जाने-अनजाने में उसे मानसिक पीड़ा दे जाते हैं। सामाजिक जागरूकता के लिए जरूरी है कि हमें हर स्तर पर इससे लड़ने के लिए तैयार होना होगा।

ज्यादातर लोग अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर एक धारणा बनाए रखते हैं। यह धारणा वे अपने अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि सुनी-सुनाई बातों के आधार पर बनाते हैं। धारणा बनाना और उससे निकलना आसान काम नहीं है, बल्कि धारणागत चीजों के कारण लोगों को कई बार अपने जीवन में खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में नुकसान उठाने से बचने के लिए लोगों को धारणा बनाने से बचना चाहिए। आमतौर पर गांव के चौक-चौराहों पर, शहर के नुक्कड़ों पर एक व्यक्ति किसी बात को लेकर अपनी धारणा पेश करता है और दूसरा व्यक्ति भी उसे उसी तरह स्वीकार कर लेता है और उसकी पुष्टि करना भी जरूरी नहीं समझता। ऐसे में हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को इसका खमियाजा भुगतना पड़े।

आखिर हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं और किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं? हमें कुंठित, विकृत, रुग्ण समाज चाहिए या फिर एक खुशहाल, समृद्ध और दुराग्रहों से मुक्त समाज चाहिए, जिसमें सभी लोग खुल कर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन कर सकें। प्रतिभा को निखार सकें। आखिर हम सभी दूसरे तरह के समाज को लेकर ही सहमत होंगे। अगर हम एक बेहतर समाज और परिवेश का निर्माण करना चाहते हैं तो हम लोगों को मिल कर विकृति, रुग्णता, कुंठा, मनोरोग फैलाने वाले लोगों की पहचान करनी होगी और ऐसे लोगों का एक सांकेतिक विरोध करना होगा। उन लोगों का मुंह बंद कराना होगा, ताकि वे अपने पूर्वाग्रहों को दूसरों तक नहीं पहुंचाएं और दुष्प्रचार न कर सकें। ऐसा होने से समाज में नित नई प्रतिभाएं सामने आएंगी और एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, जिसमें हम सभी खुल कर सांस ले सकेंगे।

खेती की खातिर

मई में किसान और उसका परिवार खेत जोतने से लेकर अन्य कृषि कार्यों में काफी व्यस्त रहता है। खरीफ फसलों के लिए इस महीने में खेत जोतना जरूरी होता है क्योंकि जून के मध्य में मानसून भारत में प्रवेश करता है जिसके बाद वह बुआई में जुट जाता है। खेत जोतने से लेकर बुआई तक किसान और उसके सहायक जम कर पसीना बहाते हैं लेकिन अधिकतर मामलों में किसान को उम्मीद के अनुसार अपने श्रम कीमत नहीं मिलती। इस वजह से वह अपने खेत बेचने या आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2015 में 8007 किसानों और 4595 खेतिहर मजदूरों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की थी। वहीं 2014 में 5650 किसानों और 6710 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या कर ली थी मगर 2015 के बाद किसान आत्महत्या की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। आज भी किसान आत्महत्या देश के लिए गंभीर समस्या है। हमारे देश में जो मध्यम और छोटे किसान हैं उनके पास जरूरी संसाधनों की कमी रहती है। जहां बड़े किसान ट्रैक्टर के जरिए आसानी से अपने विशाल खेत जोत लेते हैं वहीं मध्यम और छोटे किसान बैलों की सहायता से खेत जोतते हैं या फिर ट्रैक्टर किराए पर लेकर खेत जुतवाते हैं जिससे खेत जोतना और भी महंगा हो जाता है। गर्मियों में चारे की समस्या भी होती है जिससे उसे अपने बैलों को महंगा चारा खिलाना पड़ता है। बीज कंपनियां अपने बीजों की उत्पादन क्षमता के बड़े-बड़े दावे करती हैं लेकिन अक्सर ये दावे खोखले सिद्ध होते हैं। कई मामलों में तो बीज बोने के बाद फसल ही नहीं उगती। मध्यम और छोटे किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था न होने से उन्हें अनिश्चित मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में खेती उनके लिए एक जुआ बन जाती है जहां वे हजारों रुपए के बीज बोकर मानसून पर निर्भर रहते हैं।

ग्रामीण इलाकों में सत्तर फीसद लोगों की जीविका खेती पर निर्भर है। उनकी आय बढ़ेगी तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चलेगी। इसके मद्देनजर सरकार को कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की बदहाली दूर करने वाली नीतियां बना कर उन्हें ईमानदारी से लागू करना चाहिए। मध्यम और छोटे किसानों के लिए सिंचाई, खाद, बीज, बीमा, मिट्टी की जांच आदि की सुगम व्यवस्था करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कई योजनाएं आज भी किसान तक नहीं पहुंच पातीं या उनका जमीनी क्रियान्वयन देखने को नहीं मिलता। कर्ज माफी केवल जरूरतमंद किसानों के लिए हो और खेती में तकनीकी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। जब देश का किसान खुशहाल होगा तभी सही मायने में देश की प्रगति होगी।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली, नागपुर*

सशक्त लोकतंत्र

प्रधानमंत्री बार-बार कहते रहे हैं कि सरकार तो बहुमत से बनती है, लेकिन देश सबकी सहमति से चलता है। उनके इस कथन पर विपक्षी दलों की राय जो भी हो, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में जब देश बदल रहा है और उसकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं तब राजनीति के तौर-तरीकों में बुनियादी बदलाव की सख्त जरूरत है। सबसे अधिक जरूरत संसदीय कामकाज में बदलाव लाने की है। इस बदलाव से राजनीति का भी भला होगा। पुराने, घिसे-पिटे और निष्प्रभावी तौर-तरीकों के कारण ही भारतीय लोकतंत्र श्रेष्ठ रूप नहीं ले पा रहा है। निस्संदेह भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जरूरत तो इसकी है कि वह श्रेष्ठ और सशक्त लोकतंत्र बने।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

अभद्र बोल

हमारी आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे बेहूदा शब्द शामिल होते जा रहे हैं जिन्हें कभी जबान पर लाने पर व्यक्ति को बुरा समझा जाता था। अनेक अभद्र शब्द फिल्मों, सोशल मीडिया और आम व्यवहार में इस्तेमाल हो रहे हैं। और भी हैरानी की बात है कि ये शब्द लड़कियों और महिलाओं द्वारा भी धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं। कई फिल्मों में जब ये शब्द बोले जाते हैं तब पूरे सिनेमा हॉल में हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं, लेकिन उस समय अनेक सभ्य व्यक्ति अपने परिवार की उपस्थिति में शर्मिंदगी से नजरें झुका लेते हैं। कैसी संस्कृति होती जा रही है हमारी? हम अपनी मां-बहन-बेटियों के सामने ऐसी भाषा कैसे कह-सुन सकते हैं? फिल्म सेंसर बोर्ड इन शब्दों को कैसे मान्यता दे सकता है?

आज कुछ लोगों को अपनी बहन-बेटी को सेक्सी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती बल्कि इसे गर्व से कहा जा रहा है, लेकिन जरा गंभीरता से सोचा जाए तो उन्हें इस शब्द से घिन्न होने लगे। इन अभद्र शब्दों की सूची बड़ी है और दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कुछ समय बाद हो सकता है सार्वजनिक मंचों, पत्र-पत्रिकाओं, फिल्मों, सोशल मीडिया आदि पर खुलेआम ऐसे शब्द, मां-बहन की गलियां और अश्लील शब्द कहे जाने लगें। समाज का निर्माण हम स्वयं करते हैं और उसे अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। अब यह फैसला सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों को करना है कि अपने बच्चों को इन भौंडे शब्दों से कैसे बचाए रखना है, बचाए रखना भी है या इन शब्दों पर चुप्पी साध लेनी है अथवा इन्हें प्रोत्साहन देना है!

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

गुस्से पर काबू

लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नई केंद्र सरकार ने अपना कार्य भी आरंभ कर दिया है पर लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी भी 'इलेक्शन मोड' में चल रही हैं। ममता बनर्जी के सामने जब भी जय श्रीराम का नारा लगता है तो वे भड़क जाती हैं। इस तरह की घटनाओं की खबर पश्चिम बंगाल से लगातार आ रही है। ममता बनर्जी ने नारा लगाने वालों की खाल उधेड़ने की धमकी भी दी। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में जय श्रीराम का नारा लगाना कानूनन अपराध है? ममता बनर्जी को संयम से काम लेते हुए अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इस तरह से तो वे अपना ही नुकसान कर रही हैं।

● *बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद*